

# मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in  
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मार्च, 2023, डिसेंबर दिनांक 1 मार्च, 2023

वर्ष 66 | अंक 19 | भोपाल | 1 मार्च, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/-

## मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित की 78 करोड़ की बोनस राशि

लाइली बहना योजना से महिलाएँ होंगी सशक्त, बढ़ेगा आत्म-सम्मान

मुख्यमंत्री ने लखनादौन में 298 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि-पूजन

**भोपाल :** मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनादौन में लघु वनोपज सहकारी समिति की क्षमता वृद्धि के लिए हुए प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम में 13 वन-मण्डलों के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के तेंदूपत्ता संग्राहकों को 78 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की। साथ ही विभिन्न विभागों के 298 करोड़ 49 लाख रुपये लागत के 48 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित महुआ प्राश की लॉन्चिंग भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन उपज में आश्रित जनजातीय भाई-बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार जनजातीय बंधुओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिये लगातार प्रयास जारी है।



### सामाजिक क्रांति साबित होगी लाइली बहना योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान चौहान ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी "लाइली बहना योजना" की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहनों के लिये उपहार स्वरूप यह योजना प्रारंभ कर रहे हैं। योजना में प्रतिमाह बहनों के खातों में एक हजार रुपये की राशि डाली जायेगी। बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए यह योजना है।

बहनों के सशक्त होने से परिवार सशक्त होगा। परिवार से समाज एवं समाज से प्रदेश और देश सशक्त होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाइली बहना योजना का शुभारंभ 5 मार्च को राज्य-स्तरीय आयोजन में किया जायेगा। योजना के आवेदन के लिये बहनों को भटकना न पड़े, इसके लिये मार्च और अप्रैल माह में गाँव में ही शिविर लगा कर फॉर्म लिये जायेंगे। इसके बाद मई माह में परीक्षण कर सूची जारी की जायेगी और 10 जून से बहनों

के खातों में राशि आना शुरू हो जायेगी। उन्होंने कहा कि लाइली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति साबित होगी। योजना के लाभ से बहनों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि बहनें विवेकपूर्ण तरीके से योजना में प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए बचत भी कर सकेंगी और अच्छे कार्यों में परिवार को बेहतर सहयोग दे सकेंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरई बिजना माईक्रो इरीगेशन योजना को स्वीकृति प्रदान की। लखनादौन में खेल मैदान

बनाए जाने सहित जिले के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरीय निकाय को विकास कार्यों के लिए 2-2 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी।

### बंद होंगे सभी अहाते, मंदिर, स्कूल-कॉलेज परिसर से 100 मीटर दूरी में नहीं होंगी शराब दुकाने

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नई आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिये राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल से प्रदेश के सभी शराब अहाते बंद किए जाएंगे। साथ ही मंदिर, स्कूल, कॉलेज परिसर से 100 मीटर दूरी में कोई भी शराब दुकान नहीं खोली जायेगी।

### जनजातीय वर्ग के हितों के संरक्षण करेगा पेसा नियम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम के लागू हो जाने से जनजातीय भाई-बहनों को काफी सहूलियत होगी। उनके हितों के संरक्षण के लिये पेसा नियम लागू किया गया है। अब तेंदूपत्ता तोड़ने की जिम्मेदारी ग्रामसभा निभायेगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

## मध्यप्रदेश का सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चयन

सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों के लिए मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान

केन्द्र सरकार के सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा प्रदेश को सीबीआईपी अवार्ड प्रदान

मंत्रि-परिषद की बैठक में दी गई जानकारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान को मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बधाई दी और आभार माना



परिषद की बैठक वंदे-मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई। बैठक में मंत्रि-परिषद के सदस्यों को जानकारी दी गई कि केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्यप्रदेश को सीबीआईपी अवार्ड प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चुना गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार

व्यक्त किया। उन्होंने केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

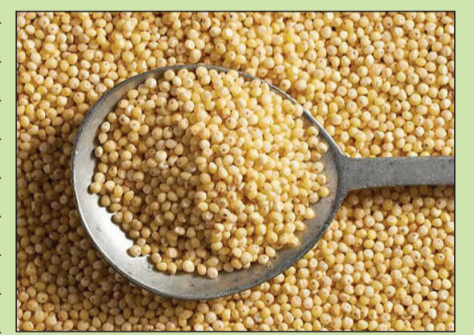
जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में विगत 15 वर्षों में सिंचाई क्षमता को 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ा कर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया गया है। विगत 3 वर्षों में मध्यप्रदेश पाईप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

मंत्रि-परिषद की बैठक में बताया कि सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों के लिए जल-संसाधनों के अधिकतम उपयोग में मध्यप्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई दी और आभार व्यक्त किया।

## मिलेट्स को बढ़ावा देने में आगे है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री श्री चौहान

**भोपाल :** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार मध्यप्रदेश मिलेट्स "श्री अन्न" को बढ़ावा देने में आगे है। आयरन और विटामिन से भरपूर मध्यप्रदेश के गेहूँ और मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्रम में एम्स भोपाल में भी मरीजों के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन में मिलेट्स को शामिल करने की पहल हुई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश का तेजस या कठिया गेहूँ कई राज्यों में जाता है। शक्ति वर्धक है, पास्ता बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इसकी विशेष माँग है। हाल ही में इन्दौर में G-20 की कृषि समूह की बैठक में भी प्रतिभागियों को मिलेट्स परोसे गए हैं। अनुसंधान में यह निष्कर्ष निकला है कि मधुमेह, मोटापा, रक्तचाप आदि समस्याओं को नियंत्रित करने में मोटे अनाजों का विशेष महत्व है।



**भोपाल :** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-

# प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में म.प्र. की कृषि विकास दर में हुआ निरंतर सुधार : मुख्यमंत्री श्री चौहान

परम्परागत मोटे अनाज के उत्पादन एवं उपयोग को अभियान के रूप में लें

कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहित करें

उत्पादन की लागत घटाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने प्रयास जारी

बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के समक्ष विचारणीय विषय



**भोपाल :** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अतिथि देवो भवः की भावना के साथ जी-20 के सम्मेलन में पधारे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जी-20 सम्मेलन का ध्येय वाक्य "एक धरती-एक परिवार-एक भविष्य" भारतीय विचार परम्परा में सदियों से विद्यमान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का श्लोक सभी के सुखी, मंगलमयी, रोगमुक्त होने और सबके कल्याण की कामना करता है। भारत जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानता और उसको क्रियान्वित करता है। जी-20 की सोच भी इसी के अनुरूप है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। विश्व का मात्र 12 प्रतिशत भू-भाग कृषि के योग्य है। वर्ष 2030 तक खाद्यान्न की माँग 345 बिलियन टन हो जाएगी, जबकि वर्ष 2000 में यह माँग 192 बिलियन टन थी। यह प्रत्यक्ष है कि न तो कृषि भूमि में वृद्धि होने वाली है और न ही हमारे प्राकृतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि कृषि योग्य भूमि का हम समुचित उपयोग भी करें और कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम उपयुक्त प्रयास भी करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं स्वयं भी एक किसान हूँ। मैंने अपनी आजीविका का निर्वहन कृषि गतिविधियों से करने का प्रण लिया है। भारत में कृषि को श्रेष्ठतम कार्य माना गया है। भारत में बड़ी संख्या में लोग आज भी कृषि कार्य में लगे हैं। मैं स्वयं भी माह में एक बार अपने खेत पर अवश्य जाता हूँ और खेती में नवाचार का प्रयास भी करता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि हमें दुनिया की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ण करना है तो हमें प्रतिबद्धता के साथ कुछ कार्य करने होंगे। पहले तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए

मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, नई तकनीक और नए बीज के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। इस दिशा में मध्यप्रदेश में लगातार प्रयास हो रहे हैं। छोटे-बड़े किसानों, महिलाओं और युवाओं को नई तकनीक के उपयोग के लिए प्रेरित करना होगा। इससे आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में एक दशक से कृषि विकास दर में निरंतर सुधार हुआ है। प्रदेश ने देश के अन्न के भंडार भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। देश में सोया के उत्पादन में 60 प्रतिशत भागीदारी मध्यप्रदेश की रही है। देश में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश, मध्यप्रदेश है। प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हमने हर संभव प्रयास किए हैं। इसमें सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के कार्य उल्लेखनीय है। वर्ष 2003 में प्रदेश में केवल साढ़े 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। इसे बढ़ा कर अब हम 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक और अच्छे बीजों के इस्तेमाल को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के साथ उत्पादन की लागत कम करना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दुनिया में हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन अनाज, फल, सब्जी का कोई विकल्प नहीं है। इनके उत्पादन के लिए हमें किसान को महत्व देना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसान को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने, उत्पादन की लागत घटाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इस दिशा में नई

किफायती टेक्नोलॉजी के उपयोग और मैकेनाइजेशन के साथ किसानों की सहायता के लिए भी उपक्रम किए जा रहे हैं। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा स्थापित किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मध्यप्रदेश ने भी अपनी ओर से राशि जोड़ी है। इसका उद्देश्य कृषि की लागत में किसान को सहयोग करना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन के उचित मूल्य दिलवाना भी आवश्यक है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लागू है। साथ ही प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान की सहायता के लिए भी राज्य और केंद्र सरकार सक्रिय हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मध्य प्रदेश में आरबीसी 6/4 में किसानों को सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि के विविधीकरण के लिए भी प्रयास आवश्यक हैं। फूल-फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी के साथ पशुपालन, मछली-पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परंपरागत मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के कार्य को अभियान के रूप में लिया है। इस गतिविधि को "श्री अन्न" का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है। हम हर संभव प्रयास करें कि यह पोषक

अनाज धरती से लुप्त न हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धरती के स्वास्थ्य की रक्षा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बेतहाशा उपयोग ने धरती के स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। भारत का सदियों से मानना है कि प्रकृति का शोषण न हो, हम केवल प्रकृति का दोहन करें। प्राकृतिक संतुलन के लिए मनुष्य के साथ ही जीव-जंतु, पशु-पक्षियों का अस्तित्व में रहना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किए गए प्राकृतिक खेती के अभियान को अपनाया जरूरी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम विश्व की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के साथ ही पृथ्वी के स्वास्थ्य, मनुष्य के स्वास्थ्य और प्रकृति के संरक्षण के लिए भी संवेदनशील हों। जो तकनीक अपनाएँ वह सभी के अस्तित्व के लिए मित्रवत हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जी-20 सम्मेलन में पधारे अतिथियों को मध्यप्रदेश के आकर्षक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का निमंत्रण भी दिया।

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, राज्यसभा सदस्य सुश्री कविता पाटीदार, सांसद श्री शंकर लालवानी, महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव, जी-20 के सदस्य देशों, अथिति देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

## किसान, गोबर और गौ-मूत्र से बनाएँ खाद : कृषि मंत्री श्री पटेल

**भोपाल :** किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से गौ-मूत्र और गोबर से खाद बना कर खेतों में उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिये हम सभी को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभानी होगी।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्राकृतिक खेती हम सभी के लिये लाभदायक है। उन्होंने बारंगा में अपने खेत पर गोबर और गौ-मूत्र से खाद भी बनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने भी अपने खेत में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है। वे गोबर, गौ-मूत्र, मिट्टी, बेसन,



वनस्पति और गुण से जीवामृत बना रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इसे बनाने में लागत भी कम आती है। उन्होंने कहा

कि कोरोना के बाद दुनिया में प्राकृतिक उत्पाद की मांग बढ़ी है।

# महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ने से हुई आर्थिक प्रगति

## मिलेट्स के उत्पादन एवं प्र-संस्करण से महिला सशक्तिकरण पर हुई कार्यशाला

**भोपाल :** महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ने से आर्थिक प्रगति हुई है। यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में केन्द्रीय कृषि महिला संस्थान भुवनेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में हुई 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर विशेषज्ञों ने कही। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट्स) वर्ष 2023 में मिलेट्स के उत्पादन एवं प्र-संस्करण से महिला सशक्तिकरण पर हुई कार्यशाला में 250 से अधिक महिला कृषक और विशेषज्ञों ने सहभागिता कर अपने अनुभव साझा किये।

समापन-सत्र में निदेशक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान डॉ. सी.आर. मेहता ने कहा कि आज देश में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके योगदान से देश प्रगति पथ



पर अग्रसर है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से आह्वान किया कि उन्हें संस्थान द्वारा विकसित फार्म एवं प्र-संस्करण यन्त्र चलाने एवं मिलेट्स के प्र-संस्कृत उत्पाद बनाने के लिए आगे आना चाहिए।

इससे महिलाओं को स्व-रोजगार और उत्तम स्वास्थ्य लाभ होगा। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय कृषि महिला संस्थान भुवनेश्वर डॉ. सबिता मिश्रा ने

बताया कि देश में विभिन्न स्थानों पर मिलेट्स आधारित प्र-संस्करण में ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ी है, जिससे उनकी आर्थिक प्रगति हुई है। प्रभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल

निकासी अभियांत्रिकी डॉ. के.वी.आर. राव ने कहा कि कम जल एवं कम उपज वाली मृदा में भी मिलेट्स का उत्पादन किया जा सकता है। वैज्ञानिक, कृषि यंत्रिकरण प्रभाग डॉ. स्वीटी कुमारी ने महिला उपयोगी कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ डॉ. अंकिता पांडेय ने मिलेट्स के विपणन और ब्रांडिंग से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी।

समापन-सत्र में विभिन्न स्थानों के महिला किसान संगठनों के प्रमुख और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान डॉ. दिपिका मुरुगकर ने पोषण संबंधी संशयों को दूर करने के लिये प्रश्नों के उत्तर दिये।

## राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना का उद्देश्य

**नई दिल्ली:** केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई-नाम पोर्टल नाम का ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध करवाया गया है। यह एक पूर्णतः डिजिटल पोर्टल है जिसके माध्यम से किसान, व्यापारी व खरीददार को एक मंच पर लाया गया है।

**राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)** पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन और अच्छे दामों में बेच सकता है। जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का मुख्य उद्देश्य विनियमित बाजार में साफ विक्रय सुविधा और उचित मूल्य के लिए एक बाजार मंच तैयार करना है।
2. कृषि उपज की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और खरीददारों द्वारा सूचित बोली सक्षम करने के लिए प्रत्येक बाजार में परख करने की क्रिया के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है।
3. इस योजना के तहत सभी व्यापारी का सभी राज्यों के लिए एक ही लाइसेंस बनाया जाता है, जो सभी बाजारों में मान्य होता है।
4. इस योजना के अंतर्गत सामान्य व्यापार के लिए गुणवत्तियों को अब तक 90 उपजों (कमोडिटी) के लिए विकसित किया गया है।

### राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के लाभ

ई-नाम पोर्टल के लाभ निम्नलिखित हैं-

1. किसानों और खरीदारों के बीच कोई बिचौलिया या दलाल नहीं आ पाता है, किसान सीधे अपने सामान को बेच व खरीद सकते हैं।
2. किसान इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फसल को बेच सकता है जिसके लिए उसको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है।
3. इस पोर्टल में देश के 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं।
4. राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होने के कारण किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलता है।
5. राज्य के स्थानीय व्यापारी के लिए मंडी में ई-नाम माध्यमिक व्यापार को राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने का अवसर प्रदान करता है।
6. ई-नाम पोर्टल कीमतों और उपलब्धता को भी स्थिर करता है।

## साँची ने बाजार में उतारे 4 नवीन दुग्ध उत्पाद

### नवीन दुग्ध उत्पाद मिष्ठी दोई, श्रीखंड लाइट, कोल्ड कॉफी और शुगर फ्री फ्लेवर्ड मिल्क बाजार में आज से होंगे उपलब्ध

**भोपाल :** प्रबंध संचालक एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन श्री तरुण राठी ने बताया है कि उपभोक्ताओं की माँग पर गुरुवार से 4 नवीन साँची दुग्ध उत्पाद बाजार में लॉन्च किए जा रहे हैं। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के 2 नवीन दुग्ध उत्पाद मिष्ठी दोई और श्रीखंड लाइट तथा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के 2 नवीन दुग्ध उत्पाद कोल्ड कॉफी और शुगर फ्री इलायची फ्लेवर्ड मिल्क 16 फरवरी 2023 से साँची पार्लरों, एजेंसियों सहित साँची आउटलेट्स पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि साँची दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रति उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। साँची के विभिन्न स्वादिष्ट दुग्ध उत्पादों की श्रृंखला में मिष्ठी दोई, श्रीखंड लाइट, कोल्ड कॉफी और शुगर फ्री फ्लेवर्ड मिल्क जुड़ गया है।

### नवीन उत्पादों की विशेषताएँ

साँची मिष्ठी दोई: घर के बने दही का स्वाद, प्रोटीन से भरपूर यह उत्पाद पाश्चुरीकृत दूध से बना हुआ है। इसमें प्रति 100 ग्राम पर 121 कैलोरी ऊर्जा, 3.5 प्रतिशत प्रोटीन, 4.5 प्रतिशत फैट होता है। सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में सेवन करने से ताजगी भरा एहसास देता है। यह 100 ग्राम कप में उपलब्ध है। इसका मूल्य 15 रूपए और शेल्फ लाइफ 4 दिन की है।



### साँची कोल्ड कॉफी

यह काफी के स्वाद से बना क्रीमी और गाढ़ा ठण्डा दुग्ध पेय पदार्थ है। इसका सेवन किसी भी समय ताजगी के लिए किया जाता है। प्रोटीन से भरपूर पेय पदार्थ में प्रति 100 ग्राम पर 75 कैलोरी, 3.5 प्रतिशत प्रोटीन, 1.7 प्रतिशत फैट है। यह पीपी बॉटल 100 एमएल पैक में उपलब्ध है। इसका मूल्य 35 रूपए और शेल्फ लाइफ 180 दिन अर्थात् 6 माह की है।

### साँची शुगर फ्री फ्लेवर्ड मिल्क

स्टेरिलिसेड इलायची वाला शुगर फ्री फ्लेवर्ड मिल्क है। इसमें प्रति 100 ग्राम पर 47 कैलोरी, 3.5 प्रतिशत प्रोटीन, 1.7 प्रतिशत फैट होता है। यह पीपी बॉटल 100 एमएल में उपलब्ध है। इसका मूल्य 30 रूपए और शेल्फ लाइफ 180 दिन

अर्थात् 6 माह की है।

### साँची श्रीखण्ड लाइट

इस उत्पाद की विशेषता यही है कि कम शक्कर वाला इलायची फ्लेवर में बनाया गया है। यह मिठाई गर्मियों में खाने में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। इसमें प्रति 100 ग्राम पर 253 कैलोरी, 8 प्रतिशत प्रोटीन और 11 प्रतिशत फैट होता है। 100 ग्राम वाले कप की शेल्फ लाइफ 10 दिनों की रखी गई है। श्री राठी ने कहा कि 'साँची' का प्रयास है कि उपभोक्ताओं को उनकी माँग के अनुरूप उच्च कोटि का दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत साँची ब्राण्ड के 4 नए उत्पाद लांच किए गए हैं। ये नवीन उत्पाद भी उपभोक्ताओं को पसंद आएंगे।

## जायद अभियान-2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन

नई दिल्ली: जायद (ग्रीष्मकालीन) अभियान-2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि खाद्यान्न के मामले में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन भारत आज जिस मुकाम पर है, वहां हम थोड़ी-सी प्रगति से संतोष नहीं कर सकते, इसमें तीव्रता आना चाहिए तथा सुचारू प्लानिंग के आधार पर ऐसे सार्थक परिणाम सामने आना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादन के रेकार्ड तोड़ अग्रिम अनुमान (323 मिलियन टन) उत्पादित करने वाले हैं।

श्री तोमर ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपलब्ध अन्य विकल्प-नैनो यूरिया, बायोफर्टिलाइजर को अपनाने पर सभी को विचार करना चाहिए। खाद सब्सिडी पर सालाना लगभग ढाई लाख करोड़ रु. खर्च हो रहे हैं, यह राशि बचाने के साथ ही स्वस्थ उत्पादन किया जा सकता है, लोगों को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। कृषि व सम्बद्ध विभाग/मंत्रालय व राज्य मिलकर टीम इंडिया



नरेंद्र सिंह तोमर  
माननीय कृषि

है, जो कृषि क्षेत्र को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन फसलें महत्वपूर्ण होती हैं, जो छोटे किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। सम्मेलन को कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा, सचिव-डेयर व महानिदेशक-आईसीएआर डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव-उर्वरक श्री अरुण बरोका ने भी संबोधित किया व अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिवों ने प्रेजेन्टेशन दिए। सम्मेलन में कृषि व अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव व राज्य के कृषि विभागों के अन्य

वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय व राज्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में बताया गया कि देश में खाद की कहीं-कोई कमी नहीं है। किसान समृद्धि केंद्रों की संख्या अब बारह हजार हो चुकी है। पीएम-प्रणाम योजना का सुचारू संचालन हो रहा है, जिसका ध्येय रासायनिक यूरिया को कम करना है। यह भी बताया गया कि केंद्र द्वारा सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम लाया जा रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पेस्टीसाइड मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा।

## भारत में यूरिया की खपत

नई दिल्ली: देश में उर्वरक की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है जबकि उत्पादन में वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से कम है। सरकार के सभी प्रयासों के बाद भी मांग और उत्पादन के अंतर में कमी नहीं हो पा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में यूरिया की मांग 335.26 लाख मै. टन और यूरिया का उत्पादन 244.55 लाख मै. टन था। मांग और उत्पादन में अंतर लगभग 90 लाख मै. टन था। वर्ष 2020-21 में मांग बढ़कर 350.64 लाख मै. टन हो गई, जबकि उत्पादन बढ़कर 246.03 लाख मै. टन ही हुआ।



इस तरह मांग और उत्पादन में अंतर बढ़कर लगभग 104 लाख मै. टन हो गया। इसी तरह 2021-22 में यूरिया की मांग 356.53 लाख मै. टन थी, जबकि उत्पादन 250.72 लाख मै. टन हुआ। मांग और आपूर्ति में अंतर लगभग 106 लाख मै. टन हो गया। चालू वर्ष 2022-23 के नौ माह (दिसंबर 2022 तक) में यह अंतर लगभग 82 लाख मै. टन पहुंच गया है। इस अवधि में 294.84 लाख मै. टन की मांग के विरुद्ध उत्पादन 210.98 मै. टन हुआ है।

मांग और उत्पादन के इस अंतर की पूर्ति के लिए सरकार की यूरिया आयात पर निर्भरता बनी हुई है। हालांकि केन्द्र सरकार का दावा है कि 6 नई यूरिया इकाइयों की स्थापना के बाद स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में 76 लाख मै. टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है।

सरकार का यह दावा कितना सच साबित होगा इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। यूरिया आयात पर निर्भरता एक ओर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाती है, वहीं समय पर यूरिया की अनुपलब्धता किसान के लिये भी पीड़ादायक साबित होती है।

## मिलेट्स फसलें विषम परिस्थितियों में भी देती हैं बेहतर उत्पादन

मध्य प्रदेश में फसलवार चिन्हित जिले



भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में म.प्र. अपनी महती भूमिका निभा रहा है। मिलेट फसलें विषम परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देती हैं। यह फसलें कम पानी, कम उर्वरक और कम कीटनाशकों के साथ कम उपजाऊ मिट्टी में भी उपज देती हैं, इसलिए इन्हें क्लाइमेट स्मार्ट अनाज कहा जाता है। मिलेट वर्ष में इन अनाजों को कई नाम दिए गए हैं जैसे मोटे अनाज, पोषक अनाज, श्रीअन्न आदि। ज्वार,

बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी फसलें राज्य के 8 संभागों के कई जिलों में ली जाती हैं जिसमें कई जिले शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक राज्य में 2021-22 में मिलेट्स के तहत ज्वार 1 लाख 24 हजार हेक्टेयर में, बाजरा 3 लाख 43 हजार हेक्टेयर में एवं कोदो-कुटकी लगभग 90 हजार हेक्टेयर में ली गई है जिसका अनुमानित उत्पादन क्रमशः 2.41 लाख टन, 8.69 लाख टन एवं 77 हजार टन होने की संभावना है।

राज्य कृषि विकास योजना के तहत राज्य मिलेट एवं जैविक मिशन को सहायता प्रोजेक्ट में जिलों में उत्पादित होने वाली फसलों का चयन किया गया है।

**कोदो-कुटकी के जिले-** जबलपुर, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, डिण्डोरी, सिंगरौली, रीवा, सीधी, सतना, बैतूल, शहडोल एवं अनूपपुर।

**बाजरा के जिले-** छिंदवाड़ा, छतरपुर, सीधी, धार, अलिराजपुर, खरगोन, बड़वानी, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी एवं दतिया।

**ज्वार के जिले-** छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, दतिया एवं बैतूल।

प्रदेश के इन जिलों में मिलेट्स फसलों पर फोकस किया जा रहा है। परम्परागत रूप से भी यहां पोषक अनाज फसलें ली जाती हैं।

## पेंशनर्स आसान प्रक्रिया से जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र

भोपाल : जिला पेंशन अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क/सीएससी जाएं। बैंक की किसी भी शाखा में सुविधा का उपयोग करें या घर पर भी ऑनलाइन के माध्यम से <http://je-evanpraman.gov.in> वेबसाइट पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। Through Face Authentication – Aadhar Face RD app गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दिये गये निर्देशों का पालन कर जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

गूगल प्ले स्टोर में उमंग एप डाउनलोड कर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन मोबाइल नम्बर एवं ओटीपी द्वारा किया जा सकता है। इसके उपरांत MPIN सेट करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु वीडियो सुविधा प्रारंभ की गई है, इस हेतु (<https://www.pensionseva.sbi./VideoLC>) वेबसाइट पर जाएं, पेंशन के जिस खाता संख्या में पेंशन जमा होती है उसकी प्रविष्टि कर सुविधा का प्रयोग करें। पोस्ट ऑफिस की सशुल्क सुविधा 70 डोर स्टेप सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसमें पोस्टमेन स्वयं पेंशनर के आवास में विजिट कर लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान करता है। जिसकी बेवासाइट (<https://www.ipponline.com/web/ppb/digital-life-certificate>) से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पेंशनर्स द्वारा अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। डिजिटल उपकरणों के अतिरिक्त पेंशनर द्वारा अपने जिले के बैंक शाखा Pension Disbursing Agency में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र मैनुअली फॉर्म जमा किया जा सकता है। आवश्यकता पढ़ने पर पेंशनर जिला पेंशन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

## पीएम-किसान योजना में किसानों को 2.24 लाख करोड़ से अधिक रु. मिले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है जो देश के किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू की गई है।

इस योजना के तहत भारत सरकार ने भारतीय किसानों और उनके परिवारों को 2.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।

इस में से 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि को कोविड लॉकडाउन के दौरान किसानों के खाते में डाला गया है और इससे देश के किसानों को उनके दिन-प्रतिदिन के खर्चों का इंतजाम करने में मदद मिली।

इस पहल के तहत वितरित किए गए धन ने किसानों के लिए क्रेडिट बाधाओं को कम करने और कृषि आदानों में निवेश में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त ग्रामीण आर्थिक विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया है।

**क्या हैं पीएम किसान योजना?**

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000/- रुपये के वित्तीय लाभ को किसानों के बैंक खातों में ट्रान्सफर किया जाता है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/यूटीएस पीएम-किसान पोर्टल पर डेटा अपलोड करने से पहले पात्र किसानों को पहचानते हैं और सत्यापित करते हैं। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपलोड किए



गए डेटा के सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाती है। पीएम-किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। संबंधित राज्य/केंद्र शासित सरकारों से मिले सत्यापित

आंकड़ों के आधार पर, केंद्र सरकार 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राशि हस्तांतरित करने में सक्षम थी। बाद के वर्षों में किसानों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है।

**पीएम किसान योजना से किसानों को मिलती आर्थिक सहायता**

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को देश भर में सभी लैंडहोल्डिंग किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है ताकि उन्हें कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के साथ-साथ खर्च करने में सक्षम बनाया जा सके।

एक किसान-केंद्रित डिजिटल

बुनियादी ढांचे ने बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया है। इस योजना ने किसानों को जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि की है, जो उन्हें जोखिम भरा लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।

IFPRI (इंटरनेशनल फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, पीएम किसान के तहत किसानों द्वारा प्राप्त धन न केवल उनकी खेती की जरूरतों में उनकी मदद कर रहे हैं, बल्कि यह उनके अन्य खर्चों जैसे कि शिक्षा चिकित्सा, विवाह, खानपान आदि के लिए भी सहायता कर रहा है। ये देश के किसानों पर योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेतक हैं।

## समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय हेतु किसान घर बैठे स्वयं कर सकते हैं पंजीयन

**रायसेन :** रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन/विक्रय हेतु किसान पंजीयन के लिए जिला उपार्जन समिति के निर्देशानुसार जिले में 114 पंजीयन केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। किसान इन पंजीयन केन्द्रों पर 28 फरवरी तक प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक पंजीयन करा सकते

हैं। मप्र शासन द्वारा किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल या कम्प्यूटर से घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं तथा ग्राम पंचायतों के सुविधा केन्द्र पर भी पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्रों

पर निजी व्यक्तियों द्वारा सायबर कैफे पर 50 रूपए शुल्क जमा कराकर प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। शासन के निर्देशानुसार सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति एवं विपणन सहकारी संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर किए जाएंगे। इस श्रेणी के सभी

किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। गेहूं पंजीयन के लिए आधार नम्बर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जाएगा। किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन कराएं। किसान की भूमि अगर अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराना होगा। किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित ई-पंजीयन पोर्टल के नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि एवं समय के स्लाट का चयन कर गेहूं का विक्रय कर सकेंगे।

## मुख्यमंत्री दुधारु पशु प्रदाय कार्यक्रम में गाय के साथ भैंस भी शामिल

हितग्राही अंशदान राशि 25 प्रतिशत से घट कर 10 प्रतिशत हुई

बैगा के साथ सहरिया और भारिया जनजाति को भी मिलेगा लाभ

भोपाल : राज्य शासन ने "मुख्यमंत्री दुधारु गाय प्रदाय कार्यक्रम" को संशोधित करते हुए "मुख्यमंत्री दुधारु पशु प्रदाय कार्यक्रम" के रूप में लागू किया है। कार्यक्रम में अब हितग्राही की मंशा अनुसार दुधारु गाय के अलावा भैंस भी प्रदाय की जा सकेगी। साथ ही कार्यक्रम का लाभ अब विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के साथ सहरिया और भारिया को भी मिलेगा। इन जनजातियों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए हितग्राही अंशदान की राशि 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई है।



पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने कहा है कि प्रति पशुपालक 2 दुधारु पशु गाय/भैंस दी जाएगी। कार्यक्रम में 90 प्रतिशत शासकीय अनुदान और 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान होगा। क्रय किये गये सभी पशुओं का बीमा होगा। मिल्क रूट और दुग्ध समितियों

का गठन मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ और पशुपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिये 750-750 गाय-भैंस प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये 29 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। गाय प्रदाय के

लिये एक लाख 89 हजार 250 रुपये और भैंस के लिये 2 लाख 43 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। गौ प्रदाय में एक लाख 70 हजार 325 रुपये शासकीय अनुदान और शेष 18 हजार 925 रुपये हितग्राही अंशदान होगा। भैंस प्रदाय में 2 लाख 18 हजार 700 रुपये

का शासकीय अनुदान और मात्र 24 हजार 300 रुपये हितग्राही का अंशदान होगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और पशुओं की दुग्ध उत्पादक क्षमता में वृद्धि, रोजगार के नवीन अवसर द्वारा हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उच्च उत्पादक क्षमता के गौ-भैंस वंशीय पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के लिये 6 जिले डिण्डोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मण्डला और बालाघाट, भारिया के लिये छिन्दवाड़ा और सहरिया जनजाति के लिये ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुरकला, मुरैना और भिण्ड जिले में कार्यक्रम क्रियान्वित होगा। हितग्राही को आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्था या दुग्ध सहकारी समिति को देना होगा। चयन के बाद हितग्राहियों को पशुपालन, पशु आहार और पशु प्रबंधन प्रशिक्षण के साथ परिचयात्मक दौरा भी करवाया जायेगा।

# जी 20 में फसलों का प्रदर्शन



**भोपाल ।** जी 20 में फसलों का प्रदर्शन-अंतरराष्ट्रीय एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप समिट (जी-20) इंदौर में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगाई जाने वाली चिन्हित फसलों एवं कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इन फसलों में छिंदवाड़ा जिले की चिरौंजी, संतरा, मिलेट्स उत्पाद, नरसिंहपुर की अरहर दाल एवं गुड़, बालाघाट का चिन्नौर

(पृष्ठ 1 का शेष)

## मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों ....

इस कार्य के लिये तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उनकी मजदूरी राज्य सरकार देगी। वनोपज जैसे हर्षा, बहेड़ा, सालबीज, आँवला आदि का संग्रहण कर इन उत्पादों को बेचने की आजादी जनजातीय भाई-बहनों के पास होगी। इससे गाँव का पैसा गाँव में ही आयेगा। आपसी विवादों को सुलझाने के लिये ग्राम शांति निवारण समिति गठित होगी, जो पंच-परमेश्वर की अवधारणा पर होगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग में लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाने की साजिश नहीं होने देंगे। धर्मान्तरण का यह कुचक्र मध्यप्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा।

### जल्द होगी एक लाख से अधिक पदों में भर्ती

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 लाख 14 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं। युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिये अनेक स्व-रोजगारमूलक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की बहने आर्थिक रूप से सशक्त हो और उनके जीवन में खुशहाली आये, यह सरकार की प्राथमिकता में है।

### किसानों के ऋण का पूरा ब्याज भरेगी सरकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कर्ज न चुका पाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों का पूरा ब्याज सरकार भरेगी तथा किसानों को बिना ब्याज के

चावल, सिवनी का जीरा संकर चावल, विदिशा का शरबती गेहूँ, इंदौर का आलू गुना की धनिया (कुंभराज लोकल) कृषि उपजों का प्रदर्शन किया गया।

कार्यक्रम में संचालनालय कृषि भोपाल के उप संचालक श्री जी.एस. चौहान, सहायक संचालक डॉ. आशुतोष पांडेय एवं जिलों के उप संचालक कृषि में छिंदवाड़ा के श्री जितेंद्र सिंह, गुना के श्री ए.के. उपाध्याय, विदिशा के श्री के. एस.

खपेडिया, मंडला की श्रीमती मधु अली, नरसिंहपुर के डॉ. आर.एन. पटेल, इंदौर के श्री शिव सिंह राजपूत एवं सहायक संचालक कृषि छिंदवाड़ा श्री सचिन जैन, गुना जिले के प्रगतिशील कृषक ग्राम बड़ोद तहसील कुंभराज के श्री गोविन्द मीणा भी उपस्थित थे।

### लहरीबाई का मिलेट्स बैंक

अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 में मोटे अनाजों के उत्पादन, उत्पादकता और संवर्धन का अभियान देश में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे

श्रीअन्न की उपमा दी है। इस श्री अन्न का संरक्षण कर उनकी श्री वृद्धि करने वाली मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के सिलपाड़ी गांव की युवा कृषक लहरी बाई को स्नेहिल आशीर्वाद देते म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। अन्नपूर्णा के रूप में लहरी बाई ने पारंपरिक मोटे अनाज की विलुप्त हो रही फसलों की लगभग 150 से अधिक किस्मों को सहेजने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी मिलेट्स बीज बैंक बनाने की इनकी लगन और जुनून को ट्वीट कर

सराहा। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्य सुरक्षा बनी रहे, इस सद्भावना से जन आंदोलन के रूप में काम कर रही लहरी बाई मिलेट्स बैंक को सुदृढ़ बनाने में अपनी जिम्मेदारी मानती हैं। इस महती कार्य में परिवार बाधा नहीं बने, इसलिए लहरी बाई ने विवाह भी नहीं किया। परन्तु अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं। इंदौर में सम्पन्न हुई जी-20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप बैठक के दौरान लगी प्रदर्शनी में डिंडोरी की लहरी बाई आकर्षण का केन्द्र रहीं।

## प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- कृषि बजट नौ साल में पांच गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ से अधिक



**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत का कृषि बजट 9 साल में पांच गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 2014 में हमारे सप्ता में आने से यह 25,000 करोड़ रुपये से कम था।

कृषि व सहकारिता क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट के बाद एक वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, भारतीय कृषि क्षेत्र आजादी के बाद लंबे समय तक संकट में रहा। देश को खाद्य सुरक्षा के लिए बाहरी देशों पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन, अब हालात बदल गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की नीतियों व किसानों के अथक प्रयासों ने देश को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज हम कई कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दलहन व तिलहन का घरेलू उत्पादन

बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। खर्च के कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 2021-22 में दालों के आयात पर 17,000 करोड़ रुपये, मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों के आयात पर 25,000 करोड़ और खाद्य तेलों के आयात पर 1.5 लाख करोड़ खर्च किए गए। कुल मिलाकर, कृषि आयात का योग करीब दो लाख करोड़ रुपये था। पीएम 11 मार्च तक ऐसे 12 वेबिनार को संबोधित करेंगे।

### सहकारिता में नई क्रांति से बदलेगी तस्वीर

प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता से देश की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में नई क्रांति हो रही है। सहकारी क्षेत्र पहले केवल कुछ राज्यों तक सीमित था अब पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा, जब तक कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को खत्म नहीं किया जाता, तब

तक पूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। मौसम के बदलाव के बारे में तत्काल जारी देने को ड्रोन इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया।

### बजट कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पर केंद्रित

पीएम ने कहा, बजट कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पर केंद्रित है। इन्हें धन आवंटित करने के लिए कोष का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या नौ साल पहले लगभग नगण्य थी, जो अब बढ़कर 3,000 से अधिक हो गई है।

### मोटे अनाज को 'श्री अन्न' के रूप में पहचान दी

2023-24 के बजट में मोटे अनाज को 'श्री अन्न' की पहचान देने का जिज्ञा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके प्रचार, प्रसार और प्रोत्साहन से छोटे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की पहल पर पूरी दुनिया इस साल 'इंटरनेशनल मिलेट्स डे' मना रही है।

- 'श्री अन्न' को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल जाने से देश के छोटे किसानों के लिए दुनिया में मोटे अनाज के विपणन का बाजार तैयार हो रहा है।

- इस क्षेत्र में स्टार्टअप के विकास की संभावना बढ़ी है। इसकी मदद से किसान दुनिया के बाजारों तक अपनी उपज को लेकर जा सकेंगे।

## राज्य संघ में सहकारिता मॉडल के अध्ययन हेतु उत्तरप्रदेश सहकारिता विभाग के 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल....



**भोपाल।** भारत सरकार में नये सहकारिता मंत्रालय के गठन के उपरांत सहकारिता क्षेत्र में व्यापक बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं इस हेतु विभिन्न प्रदेशों में सहकारिता के क्षेत्र में किये जा रहे उकृष्ट कार्यों को प्रदेश में भी क्रियान्वयन कर सहकारिता क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने एवं सदस्यों का आर्थिक उत्थान करने के लिए सहकारिता मॉडल के अध्ययन हेतु भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में उत्तरप्रदेश सहकारिता विभाग के 05 सदस्यों का प्रतिनिधियों मण्डल दिनांक 22.02.2023 को मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की शीर्षस्थ संस्था मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल में श्री अनूप कुमार द्विवेदी, सहा. आयुक्त एवं सहा. निबन्धक सहकारिता झांसी, श्री सुधीर कुमार शर्मा एडीओ हमीरपुर, श्री इन्द्र कुमार शुक्ला ए.डी.सी. ओ. चित्रकूट, श्री मान सिंह सचिव सा. सह.समि.लि. बानपुर, जिला ललितपुर, श्री राकेश सिंह सचिव तिन्दवारी कि.से.सह.स.लि. बोंदा एआईएफ का कार्य, समितियों द्वारा किये जा रहे पीडीएस के कार्यों एवं मध्यप्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में किये गये उकृष्ट कार्यों के अध्ययन हेतु प्रतिनिधि मण्डल संघ मुख्यालय भोपाल पहुंचा।

उत्तरप्रदेश सहकारिता विभाग के दल का संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, श्री संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक एवं श्री गणेश प्रसाद मांझी प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा पुष्पगुच्छ से स्वागत सत्कार किया गया। श्री रंजन एवं श्री सिंह द्वारा मध्यप्रदेश में सहकारिता के मॉडल पर चर्चा करते हुए बताया कि, सहकारिता को मजबूत करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में नवीन सहकारी समितियों का गठन एवं महत्व पर ग्रामीण एवं शहरी व्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका,

सहकारी समितियों के संचालक मण्डल के सदस्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग एवं राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग - 1 एवं 2, विभागीय कार्य मैनुअल, सहकार से समृद्धि (सफलता की 51 कहानियाँ), सहकारी पुस्तक इत्यादि का प्रकाशन किया गया है।

मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग एवं राज्य संघ के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को संगठित कर उनकी सहकारी समिति गठित करने के लिए 03 आदर्श उपविधियों का निर्माण किया गया। जिसमें -

1. प्राथमिक स्तरीय महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था (कुल 10700 पंजीकृत)
2. संकुल स्तरीय महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था (कुल 500 पंजीकृत)
3. महिला आजीविका औद्योगिक (पोषण आहार) सहकारी संघ (कुल 07 पंजीकृत)

उक्त गठित समितियों के संचालक मण्डल सदस्य को सहकारी विधान संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

मानव संसाधन के क्षेत्र में राज्य के सहकारी कर्मियों के कौशल उन्नयन हेतु राज्य संघ (अपेक्स यूनियन) के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सहायता से सहकारी समितियों के 3000 विक्रेता कर्मचारियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया। भारत में यह कार्य करने वाला मध्यप्रदेश सहकारी क्षेत्र में पीएमकेवाय से जुड़ने वाला प्रथम राज्य बन गया है।

राज्य शासन के निर्देश पर संघ

द्वारा देश के प्रथम राज्य सहकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

**मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग एवं राज्य संघ (अपेक्स यूनियन) के संयुक्त प्रयास से भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) नई दिल्ली द्वारा 22,75,97,000.00/- का Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS) प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। जिसके तहत 12 जिलों के 12 क्लस्टरों को चिन्हित कर आर्टिजन्स को कुशल एवं बाजार अनुकूल उत्पादित करने हेतु प्रशिक्षण टुल्स किट्स, राँ मटेरियल बैंक, कॉमन**

फेसिलिटी सेंटर एवं एम्पोरियम की सुविधा से उनके आर्थिक आय में वृद्धि हेतु परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत 15,000 आर्टिजन्स को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा 6,500 आर्टिजन्स को टूल किट्स उपलब्ध कराना एवं 30,000 कारीगरों के परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट योजना अंतर्गत 12 जिलों में कारीगरों को संगठित कर क्लस्टर आधारित प्राथमिक हस्तशिल्प सहकारी समितियों एवं उनके राज्य स्तरीय संघ के गठन कर कारीगरों के विकास को शाश्वत गति प्रदान करने की योजना तैयार की गई है।

संघ परिसर में संचालित हो रहे

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिनिधियों के दल द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के विषय वस्तु एवं उनके महत्व पर दल ने चर्चा की एवं कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

उत्तर प्रदेश दल के सभी प्रतिनिधियों को राज्य संघ द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण समुल्य साहित्य, पाठ्य सामग्री, ब्रोशर आदि भेंट स्वरूप प्रदान किया गया।

दल द्वारा मध्यप्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में किये जा रहे उकृष्ट कार्यों की सराहना की एवं संघ के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।

## अमित शाह की उपस्थिति में सहकारिता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए

**नई दिल्ली:** केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से पैक्स के 13 करोड़ किसान सदस्यों सहित ग्रामीण आबादी को पैक्स के माध्यम से 300 से भी अधिक सीएससी सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी।

जानकारी के मुताबिक सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पैक्स सहकारिता की आत्मा हैं और इन्हे लगभग 20 सेवाओं के प्रदाता बनाकर बहुदेशीय बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण और कृषि विकास में पैक्स की भूमिका



और योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने इस समझौते को सबके लिए विन-विन सिचुएशन बताते हुए कहा कि इससे सहकार से समृद्धि और सहकारिता को ग्रामीण विकास की रीढ़ बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न तो पूरा करने में मदद मिलेगी ही, साथ ही सहकारिता और किसान दोनों मजबूत भी होंगे। शाह ने कहा कि इससे सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) का कॉन्सेप्ट देश की छोटी से छोटी इकाई तक बेहद सरलता से पहुंच सकेगा। अमित शाह ने बताया कि पैक्स अब जल वितरण, भंडारण, बैंक मित्र सहित 20 अलग-अलग गतिविधियां चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य समान सेवा केन्द्र द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को पैक्स के

माध्यम से ग्रामीण आबादी को उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

अमित शाह ने कहा कि इस वर्ष के बजट में अगले 5 साल में 2 लाख पैक्स बनाने और हर पंचायत में एक बहुदेशीय पैक्स की रचना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की नींव भी रखी गई है। शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम लगभग 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज हुए इस समझौते के अंतर्गत पैक्स अब सामान्य सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम तो होंगी ही, इसके साथ ही पैक्स के 13 करोड़ किसान सदस्यों सहित ग्रामीण आबादी को पैक्स के माध्यम से 300 से भी अधिक सीएससी सेवाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी। इसके अलावा इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में मदद मिलेगी।

## वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधक/सहायक प्रबंधक एवं समिति के प्रतिनिधियों का नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली (NCUI) एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधक/सहायक प्रबंधक एवं प्रतिनिधियों हेतु प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन के मार्गदर्शन में "नेतृत्व विकास एवं प्रबंध" विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 20.02.2023 से 22.02.23 तक आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को सहकारिता के प्रमुख कार्य पद्धति, सहकारी समिति के पदाधिकारी/प्रबंधकों के अधिकार, कर्तव्य, समिति का प्रबंध, सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराएँ, लेखा एवं अंकेक्षण एवं वन समिति से संबंधित विषय औषधियों का "विनाश विहिन विदोहन", औषधियों का संग्रहण, औषधी प्रसंस्करण, मार्केटिंग एवं वेल्यु एडिशन, सफल उद्यमी के गुण आदि विषयों पर श्री सुधाकर पंडागरे (प्रशिक्षक), श्री सुरेश यादव (सफल उद्यमी), डॉ. सृष्टि उमेकर (विषय विशेषज्ञ), श्री अविनाश सिंह (से.नि.वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक), श्री संजय कुमार सिंह (महाप्रबंधक, म.प्र.रा.सह.संघ), श्री भगवान सिंह राठौर (वरिष्ठ प्रशिक्षक रुडसेटी), श्री श्रीकुमार जोशी, (सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता), श्री



आनंद पराडकर विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के तृतीय दिवस सभी प्रतिभागियों को अध्ययन भ्रमण हेतु भारतीय अनुसंधान परामर्श केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को श्री संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम के सत्र समन्वयक श्री मो. शाहिद खान प्रशिक्षक, श्रीमती रेखा पिप्पल व्याख्याता, श्रीमती मीनाक्षी बान कम्प्यूटर व्याख्याता, श्रीमती

श्रद्धा श्रीवास्तव प्रशिक्षिका, श्री प्रवीण कुशवाह एवं श्री विक्रम मुजुमदार, के सहयोग से संपन्न किया गया।

## महिला सहकारी समितियों हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन



भोपाल। श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली से प्रायोजित एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के आयोजन में विदिशा जिले की महिला सहकारी समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु "नेतृत्व विकास" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 20.02.20.23 से 23.02.2023 तक किया गया। प्रशिक्षण में विषय की सारगर्भिता को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अतिथि वक्ताओं के द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिये गये। डॉ. आनंद पराडकर द्वारा अंकेक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान, श्रीमति प्रतिभा तिवारी द्वारा उद्यमिता विकास, श्री नीरज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि द्वारा "इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता"(E-BAAT) पर, श्री भगवान सिंह सीनियर फेकल्टी रुडसेट संस्थान भोपाल द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार, डॉ. सृष्टि उमेकर मोटिवेशन स्पीकर द्वारा व्यक्तित्व विकास, सम्प्रेषण कला, समय प्रबंधन, विषयों पर व्याख्यान दिया गया।

प्रशिक्षण में द्वितीय दिवस संध्या कालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमति अनुराधा भाटिया सेवानिवृत्त वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, केन्द्रीय भूमि जल



बोर्ड, भारत संस्कार जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं श्रीमति अंजली शुक्ला रिटायर्ड कैशियर बैंक ऑफ बड़ोदा का स्वागत अभिनंदन श्रीमति धनिया बाई और रामश्री केवट द्वारा किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंगोली एवं मेहेंदी प्रतियोगिता भी रखी गयी जिसमें रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्रीमती लक्ष्मी जाटव और श्रीमती धनिया बाई ने प्राप्त किया एवं मेहेंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्रीमती रानी प्रजापति ने प्राप्त किया जिन्हें पुरस्कार स्वरूप राज्य संघ का स्मृती चिन्ह मुख्य अतिथियों द्वारा प्रदाय किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय दिवस प्रतिभागियों को अध्ययन भ्रमण हेतु केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में कराया गया।

डॉ. प्रकाश पी. अम्बालकर चीफ टैक्नीकल ऑफिसर ICAR-

CIAE भोपाल द्वारा अध्ययन भ्रमण में सोयाबीन से बनने वाले उत्पाद जैसे- टोफू, दुध, मट्ठा, दही, कुकीज इत्यादि के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी महिला प्रतिभागियों को सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश से पधारें अधिकारी एवं पदाधिकारी तथा श्री संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक द्वारा प्रमाण पत्र प्रदाय किये गये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्रीमति मीनाक्षी बान कम्प्यूटर व्याख्याता एवं श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। श्रीमति रेखा पिप्पल, लेखा अधिकारी, श्री धनराज सैदाणे, श्री विनोद कुशवाह एवं कार्यालय के सभी सदस्यों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित किया गया।



### म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित

(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)

माध्यम - ऑनलाईन

योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/ प्रवेश की अंतिम तिथि - 28 फरवरी 2023

कुल फीस - 20200/-

ऑनलाईन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के पोर्टल [www.mpscuonline.in](http://www.mpscuonline.in) पर विजिट करें।

संपर्क :-

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160, 2926159

मो. 8770988938, 9826876158

Website-[www.mpscu.in](http://www.mpscu.in), Web Portal-[www.mpscuonline.in](http://www.mpscuonline.in)

Email-[rajyasanghbpl@yahoo.co.in](mailto:rajyasanghbpl@yahoo.co.in)

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन - 452006

फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053

Email - [ctcindore@rediffmail.com](mailto:ctcindore@rediffmail.com)

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001

मो. 9424782856, 8827712378

Email - [ctcjabalpur@gmail.com](mailto:ctcjabalpur@gmail.com)

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव

जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन - 471201

9424782856, 9755844511

Email - [ctcnogong@gmail.com](mailto:ctcnogong@gmail.com)